



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, सोमवार, 13 जनवरी, 2014 / 23 पौष, 1935

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जनवरी, 2014

**संख्या मुद्रण (बी) 10-4/2011.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 27-12-2012 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जिल्दसाज़, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जिल्दसाज़, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध "क" का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जिल्दसाज़, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के उपाबन्ध 'क' में :—

स्तम्भ संख्या 15—क में : (VII) निबन्धन और शर्तों के खण्ड (ड) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

"संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।"

3. **उपाबन्ध "ख" का संशोधन.**—"उक्त नियमों" के उपाबन्ध 'ख' में विद्यमान निबन्धन और शर्तों संख्या : 6 के उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

आदेश द्वारा  
मनीषा नंदा,  
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

[Authoritative English Text of this department Notification No: Mudran (B)10-4-2011 Dated 9-1-2014, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 9<sup>th</sup> January, 2014

**No: Mudran (B)10-4/2011.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Binder, Class-III** (Non-Gazetted) (Non-Ministerial-Services), Recruitment and Promotion Rules, 2012, notified *vide* Notification of even number dated 27-12-2012, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Binder, Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial-Services), Recruitment and Promotion (1<sup>st</sup> Amendment) Rules, 2014.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure “A”.**—In Annexure “A” to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Binder, Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial-Services), Recruitment and Promotion Rules, 2012, (hereinafter referred to as the said rules);

for the existing provisions against the Col No.15-A VII (e) of the said rules, the following shall be substituted namely;

“An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.”

**4. Amendment of Annexure “B”.**—In Annexure “B” to the said rules, for the existing terms and condition No: 6, the following shall be substituted, namely :—

“An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.”

By order,  
MANISHA NANDA,  
Pr. Secretary (P&S).

## PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

### CORRIGENDUM

*Shimla-2, the 9<sup>th</sup> January, 2014*

**No: Mudran (B)10-4/2011.**—In the English version of Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Binder, Class-III** (Non-Gazetted) (Non-Ministerial-Services) Recruitment and Promotion Rules, 2012, notified *vide* this Department Notification of even number dated 27-12-2012, published in the Himachal Pradesh Rajpatra dated 28-1-2013, in the provision against Col. No: 15-A, for the words, “appointment to the”, words “appointment to the post” shall be substituted.

By order,  
MANISHA NANDA,  
Pr. Secretary (P&S).

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जनवरी, 2014

**संख्या : मुद्रण (बी)10-9/2010.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 27 दिसम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, **डिवैलपर, वर्ग-III** (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, डिवैल्पर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध "क" का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग डिवैल्पर, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है, के उपाबन्ध 'क' में :

स्तम्भ संख्या 15—क में क्रम संख्या (VII) निबन्धन और शर्तों के खण्ड (ड) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो"।

3. **उपाबन्ध "ख" का संशोधन.**—"उक्त नियमों" के उपाबन्ध "ख" में विद्यमान निबन्धन और शर्तों संख्या: 6 के उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो"।

आदेश द्वारा,  
मनीषा नंदा,  
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

[Authoritative English Text of this department Notification No: Mudran (B)10-9-2010 Dated 9-1-2014, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 9<sup>th</sup> January, 2014

**No: Mudran (B)10-9/2010.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Developer, Class-III** (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012 in the department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh notified vide Notification of even number dated 27-12-2012.

1. **Short Title and Commencement.**—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department **Developer, Class-III (Non-Gazetted)** Recruitment and Promotion (**1<sup>st</sup> Amendment**) Rules, 2014.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure-“A”.**—In Annexure “A” to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Developer, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules);

For the existing clause (e) of the terms and conditions against the provisions of Col. No.15-A (VII), the following shall be substituted, namely;

“An official appointed on contract basis who has completed **three** years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.”

**4. Amendment of Annexure “B”.**—In Annexure “B” of the said rules, for the existing terms and condition No:6, the following shall be substituted namely:—

“An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.”

By order,  
MANISHA NANDA,  
*Pr. Secretary (P&S).*

## PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

### CORRIGENDUM

*Shimla-2, the 9<sup>th</sup> January, 2014*

**No: Mudran (B)10—9/2010.**—In the English version of Recruitment and Promotion Rules for the post of **Developer, Class-III** (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012 notified *vide* this Department Notification of even number dated 27-12-2012, and published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 28-1-2013, in the existing proviso of Clause (c) of the Terms and Conditions, against Col. No: 15-A (VII) of the said rules, for the words, “unavailed” words “unavailed” shall be substituted.

By order,  
MANISHA NANDA,  
*Pr. Secretary (P&S).*

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जनवरी, 2014

**संख्या: मुद्रण (बी)10—25 / 2010.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन), वर्ग—I, (राजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन), वर्ग—I (राजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 हैं ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उपाबन्ध “क” का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग उप नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन), वर्ग—I (राजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त” नियम कहा गया है) के उपाबन्ध ‘क’ में स्तम्भ संख्या: 15—क (VII)(ड) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो” ।

3. **उपाबन्ध “ख” का संशोधन.**—उक्त नियमों के उपाबन्ध ‘ख’ में निबन्धन और शर्तें संख्या: 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्:—

“संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।”

आदेश द्वारा,  
मनीषा नंदा,  
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

[Authoritative English Text of this department Notification No:- Mudran(B)10-25/2010  
Dated 9-1-2014, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

## PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 9<sup>th</sup> January, 2014

**No:Mudran (B)10-25/2010.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Deputy Controller (Printing and Stationery), Class-I** (Gazetted), (Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules, 2012, notified *vide* Notification of even number dated 10-12, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Deputy Controller (Printing and Stationery), Class-I (Gazetted ), (Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion (Ist Amendment) Rules, 2014.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure "A".**—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Deputy Controller (Printing and Stationery), Class-I (Gazetted ), (Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules, 2012 (herein after referred to as the said rules), for the existing provisions against the Col.No:15-A VII(e), the following shall be substituted, namely:—

“An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.”

**3. Amendment of Annexure "B".**—In Annexure "B" to the said rules, for the provisions against the terms and condition No: 6, the following shall be substituted, namely:—

“An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds”.

By order,  
MANISHA NANDA,  
Pr. Secretary (P&S).

## मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जनवरी, 2014

**संख्या: मुद्रण(बी)10-42/2010.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 27 दिसम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, **भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम 2014 हैं।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग भाण्डागारिक (वेयर हाऊस ऑपरेटर), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के उपाबन्ध 'क' में, स्तम्भ संख्या 15-क में क्रम संख्या (VII) निबन्धन और शर्तों के खण्ड (ड) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

“संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ”।

3. उपाबन्ध "ख" का संशोधन.—उक्त नियमों के उपाबन्ध 'ख' में विद्यमान निबन्धन और शर्तें संख्या: (6) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो" ।

आदेश द्वारा,  
मनीषा नंदा,  
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

[Authoritative English Text of this department Notification No: **Mudran (B)10-42/2010**  
Dated 9-1-2014, As required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

## PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 9<sup>th</sup> January, 2014*

**No: Mudran (B)10-42/2010.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Recruitment and Promotion Rules for the post of, **Ware House Operator, Class-III** (Non Gazetted), Non-Ministerial Services, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh, notified *vide* Notification of even number dated 27-12-2012, namely :—

**1. Short Title and Commencement.**—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department **Ware House Operator, Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2014.**

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure- "A".**—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Ware House Operator, Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2012 (herein after referred to as the said rules) ;

for the existing clause (e) of the terms and conditions, against provisions of Col. No.15 A (VII), the following shall be substituted, namely :—

"An official appointed on contract basis who has completed **three** years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds."

**4. Amendment of Annexure "B".**—In Annexure "B" of the said rules, for the existing terms and condition No: 6, the following shall be substituted, namely:—



“An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.”

By order,  
MANISHA NANDA,  
Pr.Secretary(P&S).

## लोक निर्माण विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 10 जनवरी, 2014

**सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ-5) 17 / 2013.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बनीयाला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फ़िल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फ़िल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	रकवा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	बनीयाला	89	0-4
			90 / 1	0-1
			91 / 1	0-4
			92 / 1	0-1
			93	0-4
			94 / 1	0-2
			584 / 98	0-1
			585 / 98	0-0 कम अज विस्वा
			99 / 1	0-0-6
			113 / 1	0-2
			113 / 2	0-2
			121	0-3
			किता: 12	1-4-6

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 10 जनवरी, 2014

**सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ-5) 21/2013.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कुनपलेट, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

## विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकबा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	कुनपलेट	320 / 229 / 1	0-2
			231 / 1 जखीरा द्रखतान	0-17
			433 / 235 / 2 / 1	0-13
			425 / 234 / 2 / 1	0-10
			245 / 1 जखीरा द्रखतान	0-3
			245 / 2 जखीरा द्रखतान	0-11
			246 / 1	0-6
			467 / 465 / 477 / 236 / 1	0-12
			468 / 248 / 1	0-1
			469 / 248 / 1 / 1	0-5
			445 / 418 / 249 / 1	0-3
			445 / 418 / 249 / 2	0-2
			238 / 2 / 1	1-14
			417 / 249 / 1	0-14
			239 / 2 / 1	0-5
			250 / 1	0-2
			240 / 2 / 1	0-6
			269 / 1	1-10
			269 / 2	0-5
			289 / 243 / 2 / 1	1-4
			किता: 20	10-5

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 10 जनवरी, 2014

**सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ-5) 22/2013.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव उंटपुर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

## विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकवा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	उंटपुर	366 / 1	1-19
			363 / 1	4-17
			362 / 1	1-2
			361 / 1	0-4
			357 / 1	1-18
			16 / 1	0-16
			16 / 2	0-3
			15 / 2 / 1	0-12
			15 / 1 / 1	0-9
			17 / 1	3-3
			12 / 1	1-11
			13 / 1	0-12
			13 / 4	0-9
			6 / 1	3-6
			4 / 1	0-10
			3 / 1	1-7
			390 / 1	2-0
			393	0-9
			389 / 1	1-13
			386 / 1	0-18
			395 / 1	1-10
			396 / 1	1-3
			397 / 1	0-6

			414 / 1	2-7
			415 / 1	1-3
			416 / 1	1-13
			419 / 1	1-15
			420 / 1	0-7
			14 / 1	0-12
			375 / 1	0-12
			394 / 1	0-5
			किता: 31	39-11

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / -  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 10 जनवरी, 2014

**सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ-(5) 23 / 2013.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव नाल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बददी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकवा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	नाल	4	0-7
			3	1-4
			2 / 1	0-5
			5 / 1	0-8
			7 / 1	0-8
			8	0-5
			10 / 1	0-18

			36 / 1	0—3
			48 / 1	0—14
			18 / 1	0—8
			50 / 1	0—10
			53	0—7
			54	0—5
			68 / 1	0—14
			55 / 1	0—1
			61 / 1	0—4
			88 / 1	0—7
			280 / 90 / 1	0—7
			281 / 90 / 1	0—7
			279 / 90 / 1	0—2
			276 / 65	0—2
			278 / 65 / 1	0—3
			278 / 65 / 2	0—1
			64 / 1	0—11
			95 / 1	0—13
			96 / 1	0—17
			97 / 1	0—18
			101 / 1	3—0
			109 / 1	1—9
			114 / 1	2—8
			274 / 163	0—10
			275 / 163 / 1	1—18
			275 / 163 / 2	0—4
			205 / 1	0—6
			206 / 1	0—3
			208 / 1	0—13
			209 / 1	0—7
			210	0—2
			201 / 1	0—17
			214 / 1	0—8
			218 / 1	0—8
			219 / 1	0—4
			195 / 1	0—12
			225 / 1	1—7
			268 / 227 / 2 / 1	0—7
			271 / 249 / 2 / 1	0—17
			252 / 1	0—9
			251 / 1	0—15
			222 / 1	0—17
			किता: 49	29—10

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

**लोक निर्माण विभाग**

शिमला-2 10 जनवरी, 2014

**अधिसूचना**

**सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ-5) 24 / 2013.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बाहा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

**विवरणी**

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकवा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	बाहा	7 / 2 / 1	0-5
			6	0-9
			किता: 2	0-14

आदेश द्वारा  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

**लोक निर्माण विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 10 जनवरी, 2014

**सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ-5) 26 / 2013.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव ढलाथों, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

## विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकवा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	ढलाथों	57	0-7
			किता: 1	0-7

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## लोक निर्माण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 10 जनवरी, 2014

**सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ—(5) 30/2013.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव थाना, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग—21ए पिन्जौर—बद्दी—नालागढ़—स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

## विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकवा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	थाना	15 / 1	0-7
			16 / 1	1-1
			26 / 1	0-6
			26 / 2	0-6
			87	0-4
			94	0-4
			93 / 1	0-1
			95 / 1	0-3
			97 / 1	0-9
			98 / 1	0-7
			किता: 10	3-8

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA****NOTIFICATION***Shimla, the 10<sup>th</sup> January, 2014*

**No. HPERC/Secy/151.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 92 and clause (zl) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following amendment in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005, namely:—

**REGULATIONS**

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (Seventh Amendment) Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Regulation 2.**—In regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005 (hereinafter referred as “the said regulations” after clauses (c) and (i), the following clauses (ca) and (ia) shall be respectively added, namely:—

“(ca) **“interlocutory application”** means an application filed in any petition or proceeding already instituted before the Commission, but does not include an application for review;

(ia) **“review petition”** means the petition filed by any person under section 94(1) of the Act or regulation 63 of these regulations or any subsequent enactment thereof for review of the order or decision or directions of the Commission;”.

**3. Amendment of Regulation 11.**—After sub-regulation (2) of regulation 11 of the said regulations, the following proviso shall be added:—

“Provided that where the Commission initiates *suo-motu* proceedings, the notice inviting public response shall clearly indicate the proposal of the Commission and shall be inserted/uploaded/published in public domain for seeking suggestions and objections of the public.”

**4. Amendment of Regulation 22.**—In sub-regulation (7) of regulation 22 of the said regulations, after the word “communicated” the words “within seven days” shall be inserted.

**5. Insertion of Regulations 24-A and 24-B.**—At the end of Chapter-II of the said regulations, the following new regulations 24-A and 24-B shall be inserted, namely:—

**“24-A. Register of Petitions/Appeals.**—(1) A register in Form CB 12-A (Annexure-XA) shall be maintained in regard to the petitions and appeals filed against the orders, decisions or directions of the Commission—

(i) before the High Court;

(ii) before the Appellate Tribunal for Electricity; or

(iii) before the Supreme Court of India;



and necessary entries' therein be promptly made in the Judicial Section of the Commission.

- (2) The register shall be placed for scrutiny by the Chairperson in the first week of every month.

**24-B. Placing of Supreme Court/High Court/Appellate Tribunal Orders before the Commission.**—Whenever an interim or final order passed by the Supreme Court of India, or the Appellate Tribunal for Electricity or the High Court in any petition or appeal or other proceeding preferred against the order, decision or direction of the Commission is received, the same shall forthwith be placed before the Chairperson/Members for information and kept in the relevant case file. Immediate attention of the Secretary shall be drawn to the directions requiring compliance and it shall be the duty of the Secretary to take expeditious steps to comply with the directions of the Supreme Court of India, High Court or the Appellate Tribunal for Electricity as the case may be”.

**6. Amendment of Regulation 26.**—In sub-regulation (3) of regulation 26 of the said regulations, after the word “proceedings” the words “and or by the beneficiaries of technical feasibility studies/general studies in proportion to the benefit to be derived by them” shall be inserted.

**7. Amendment of Schedule.**—In the Schedule to the said regulations.—

- (A) the existing serial No. 1 shall be renumbered as serial No. 1-a and before renumbered serial No.1-a, the following serial No. 1 shall be inserted, namely.—

“1. Application/processing fee for grant of licence under the Act.	CBR 27	₹ 1 lakh or any such other amount as may be prescribed by the State Govt. under section 15 of the Act;”
--	--------	---

- (B) in renumbered serial No.1-a.—

- (a) against item (iii) for figure and words “25 lakh per annum”, the words and figures “₹1 lakh minimum for 100 MUs or less plus ₹50,000/- for every additional 50 MUs or part thereof”, shall be substituted;
- (b) item (v) shall be omitted; and
- (c) in item (vi) clause (c) shall be omitted;

- (C) for serial No. 2, the following serial No. 2 shall be substituted, namely:—

**Tariff determination—**

**(a) Hydel Projects-**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| (i) Application for determination of initial capital cost including tariff in respect of Hydro generating station above 25 MW. | Sections 62, 64 and 86(1) (a) & (b) of the Act, CBR 12 (5) | (i) ₹15 Lakhs plus ₹ 20,000/- for every additional 1.00MW or part thereof exceeding 25 MW capacity subject to maximum ₹ 25 Lakhs. |
|--|--|---|

(ii) Additional capitalization of capital cost.

(ii) 30% of the fee paid for tariff determination under item (i) above.

**(b) Renewable energy generation projects-**

Project specific levellised tariff determination of renewable energy generating projects (all renewable sources).

Section 62, 64 & 86(1) (a) of the Act, CBR 12(5)

- (i) above 100KW upto 2.00 MW
- (ii) above 2.00MW upto 5.00MW
- (iii) above 5.00MW upto 25MW.

(i) ₹ 2 Lakhs.  
(ii) ₹ 5 Lakhs.  
(iii) Minimum ₹ 6 Lakhs plus ₹ 20,000/- for any additional 1 MW or part thereof exceeding 5 MW capacity.”

**(D)** for serial No. 5, the following serial Nos. 5, 5A, 5B, 5C and 5D shall be substituted, namely:—

5. Application fee for determination of cross subsidy surcharge and additional surcharge for open access consumer(s)/user(s).

Section 42(2) of the Act

₹ 3 lakh

- 5.A SLDC Charges  
Application fee for determination of SLDC charges (ARR).

₹ 2 Lakh

- 5.B Application for adoption of Tariff under Section 63 of the Act.

Section 63 of the Act

(i) ₹ 5 Lakh for renewable energy (to be shared equally between the contracting parties).  
(ii) ₹ 10 Lakh for conventional energy (to be shared equally between the contracting parties).

- 5.C Application for adjudication of dispute regarding provision of non-discriminatory open access under Section 39(2) (d), 40(c) and 42(2) of the Act, if such dispute is not resolved by SLDC/Nodal Agency.

Section 39(2)(d), 40(c) and 42(2) of the Act

(i) For connectivity, long-term and medium-term open access related issues-  
a) upto 5.00 MW fee ₹ 20000/-.  
b) above 5.00 MW fee ₹ 50,000/-.  
(ii) for connectivity and short-term open access related issues-  
a) upto 5.00 MW fee ₹ 10,000/-  
b) above 5.00 MW fee ₹ 20,000/-

	5.D	Application fee for average pooled purchase cost determination.		₹ 2 Lakh.”
(E)	in existing serial No. 7, against clause (a) of sub-item (i), for the figure “Rs. 50,000/-”, the figure and words “10% of the fee paid for tariff determination” shall be substituted.			
(F)	for serial No. 10, the following serial No. 10 shall be substituted:—			
	“10.	Applications under clause (f) of sub-section(1) of section 86 for entertaining and adjudicating disputes between licensees and generating companies and between the licensees themselves.	Section 86(1)(f) of the Act	“(i) For renewable energy related petition (a) upto 2 MW ₹ 10,000/-, (b) above 2 MW and upto 5 MW, ₹ 20,000/-, (c) for above 5 MW not exceeding 25 MW ₹ 50,000/-. (ii) for conventional energy generation related petition exceeding 25MW ₹ 2 lakh”, (iii) for any other case not covered above ₹ 2 lakh”.
(G)	for serial No. 14, the following serial No. 14 shall be substituted, namely:—			
		“Any other issue of miscellaneous nature to be decided/adjudicated upon by the Commission not covered elsewhere.		(i) Individual consumer ₹ 5,000/-, (ii) Other than individual consumer ₹ 20,000/-”.

**8. Insertion of Annexure-XA.**—After Annexure-X to the said regulations, the following Annexure-X-A shall be inserted, namely:—

**“ANNEXURE-X-A  
FORM-CB-12A  
(See regulation 24-A CBR)**

**REGISTER OF PETITIONS/APPEALS TO HIGH COURT/APPELLATE TRIBUNAL  
FOR ELECTRICITY/SUPREME COURT OF INDIA**

Sl. No.	Petitions No. before the High Court	Appeal No. before the Appellate Tribunal for Electricity	SLP/Appeal No. before the Supreme Court of India	Name of the Appellant/ Respondent	Date of dispatch of records to the High Court/ Appellate Tribunal for Electricity/ Supreme Court of India	Date of records of receipt from the High Court/ Appellate Tribunal for Electricity/ Supreme Court of India
1	2	3	4	5	6	7
	Petitions/Appeal dismissed/allowed with date	Interim directions, if any, with date	Final order on the petition appeal with date	Directions, if any, for compliance issued by the Appellate Tribunal for Electricity	Steps taken for compliance	Remarks”
	8	9	10	11	12	13

By order of the Commission  
Sd/-  
Secretary.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2013/ पौष 14, 1934 (शक)  
No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2013/PAUSA 14, 1934 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

*New Delhi, the 4th January, 2013/Pausa 14, 1934 (Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 3rd January, 2013, and is hereby published for general information.

### THE PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING (AMENDMENT) ACT, 2012

(No. 2 OF 2013)

[3rd January, 2013.]

An Act further to amend the Prevention of Money-laundering Act, 2002.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Prevention of Money-laundering (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

15 of 2003.

2. In section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1),—

(i) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

“(fa) “beneficial owner” means an individual who ultimately owns or controls a client of a reporting entity or the person on whose behalf a transaction is being conducted and includes a person who exercises ultimate effective control over a juridical person;”;

(ii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ha) “client” means a person who is engaged in a financial transaction or activity with a reporting entity and includes a person on whose behalf the person who engaged in the transaction or activity, is acting;”;

Short title  
and  
commence-  
ment.

Amendment  
of section 2.

(iii) after clause (i), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(ia) “corresponding law” means any law of any foreign country corresponding to any of the provisions of this Act or dealing with offences in that country corresponding to any of the scheduled offences;

(ib) “dealer” has the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Central Sales Tax Act, 1956;”

74 of 1956.

(iv) clause (ja) shall be omitted;

(v) for clause (I), the following clause shall be substituted, namely:—

“(I) “financial institution” means a financial institution as defined in clause (c) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 and includes a chit fund company, a housing finance institution, an authorised person, a payment system operator, a non-banking financial company and the Department of Posts in the Government of India;”

2 of 1934.

(vi) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely:—

“(n) “intermediary” means,—

(i) a stock-broker, sub-broker, share transfer agent, banker to an issue, trustee to a trust deed, registrar to an issue, merchant banker, underwriter, portfolio manager, investment adviser or any other intermediary associated with securities market and registered under section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992; or

15 of 1992.

(ii) an association recognised or registered under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 or any member of such association; or

74 of 1952.

(iii) intermediary registered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority; or

(iv) a recognised stock exchange referred to in clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;”

42 of 1956.

(vii) in clause (q), the words “and includes a person carrying on designated business or profession” shall be omitted;

(viii) in clause (ra), in sub-clause (i), for the word “remits”, the words “transfers in any manner” shall be substituted;

(ix) after clause (s), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(sa) “person carrying on designated business or profession” means,—

(i) a person carrying on activities for playing games of chance for cash or kind, and includes such activities associated with casino;

(ii) a Registrar or Sub-Registrar appointed under section 6 of the Registration Act, 1908, as may be notified by the Central Government;

16 of 1908.

(iii) real estate agent, as may be notified by the Central Government;

(iv) dealer in precious metals, precious stones and other high value goods, as may be notified by the Central Government;

(v) person engaged in safekeeping and administration of cash and liquid securities on behalf of other persons, as may be notified by the Central Government; or

(vi) person carrying on such other activities as the Central Government may, by notification, so designate, from time to time;

(sb) "precious metal" means gold, silver, platinum, palladium or rhodium or such other metal as may be notified by the Central Government;

(sc) "precious stone" means diamond, emerald, ruby, sapphire or any such other stone as may be notified by the Central Government;';

(x) after clause (v), the following shall be inserted, namely:—

*'Explanation.*—For the removal of doubts, it is hereby clarified that the term "property" includes property of any kind used in the commission of an offence under this Act or any of the scheduled offences;

32 of 1994.

(va) "real estate agent" means a real estate agent as defined in clause (88) of section 65 of the Finance Act, 1994;';

(xi) after clause (w), the following clause shall be inserted, namely:—

*'(wa)* "reporting entity" means a banking company, financial institution, intermediary or a person carrying on a designated business or profession;';

3. In section 3 of the principal Act, for the words "proceeds of crime and projecting", the words "proceeds of crime including its concealment, possession, acquisition or use and projecting or claiming" shall be substituted. Amendment of section 3.

4. In section 4 of the principal Act, the words "which may extend to five lakh rupees" shall be omitted. Amendment of section 4.

5. In section 5 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of section 5.

*"(1)* Where the Director or any other officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of this section, has reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing), on the basis of material in his possession, that—

(a) any person is in possession of any proceeds of crime; and

(b) such proceeds of crime are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of crime under this Chapter,

he may, by order in writing, provisionally attach such property for a period not exceeding one hundred and eighty days from the date of the order, in such manner as may be prescribed:

2 of 1974.

Provided that no such order of attachment shall be made unless, in relation to the scheduled offence, a report has been forwarded to a Magistrate under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973, or a complaint has been filed by a person authorised to investigate the offence mentioned in that Schedule, before a Magistrate or court for taking cognizance of the scheduled offence, as the case may be, or a similar report or complaint has been made or filed under the corresponding law of any other country:

Provided further that, notwithstanding anything contained in clause (b), any property of any person may be attached under this section if the Director or any other officer not below the rank of Deputy Director authorised by him for the purposes of this section has reason to believe (the reasons for such belief to be recorded in writing), on the basis of material in his possession, that if such property involved in money-laundering is not attached immediately under this Chapter, the non-attachment of the property is likely to frustrate any proceeding under this Act."

6. In section 8 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), after the words and figure "section 5, or, seized", the words "or frozen" shall be inserted;

Amendment of section 8.

(ii) in sub-section (3),—

(a) in the opening portion, for the words and figures “record seized under section 17 or section 18 and record a finding to that effect, such attachment or retention of the seized property”, the words and figures “record seized or frozen under section 17 or section 18 and record a finding to that effect, whereupon such attachment or retention or freezing of the seized or frozen property” shall be substituted;

(b) in clause (a), for the words “scheduled offence before a court; and”, the words “offence under this Act before a court or under the corresponding law of any other country, before the competent court of criminal jurisdiction outside India, as the case may be; and” shall be substituted;

(c) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) become final after an order of confiscation is passed under sub-section (5) or sub-section (7) of section 8 or section 58B or sub-section (2A) of section 60 by the Adjudicating Authority”;

(iii) in sub-section (4), for the words “possession of the attached property”, the following shall be substituted, namely:—

“possession of the property attached under section 5 or frozen under sub-section (1A) of section 17, in such manner as may be prescribed:

Provided that if it is not practicable to take possession of a property frozen under sub-section (1A) of section 17, the order of confiscation shall have the same effect as if the property had been taken possession of.”;

(iv) for sub-sections (5) and (6), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(5) Where on conclusion of a trial of an offence under this Act, the Special Court finds that the offence of money-laundering has been committed, it shall order that such property involved in the money-laundering or which has been used for commission of the offence of money-laundering shall stand confiscated to the Central Government.

(6) Where on conclusion of a trial under this Act, the Special Court finds that the offence of money-laundering has not taken place or the property is not involved in money-laundering, it shall order release of such property to the person entitled to receive it.

(7) Where the trial under this Act cannot be conducted by reason of the death of the accused or the accused being declared a proclaimed offender or for any other reason or having commenced but could not be concluded, the Special Court shall, on an application moved by the Director or a person claiming to be entitled to possession of a property in respect of which an order has been passed under sub-section (3) of section 8, pass appropriate orders regarding confiscation or release of the property, as the case may be, involved in the offence of money-laundering after having regard to the material before it.”.

Amendment  
of section 9.

7. In section 9 of the principal Act,—

(i) in the opening portion, for the words, brackets and figures “sub-section (6) of section 8”, the words, brackets, figures and letter “sub-section (5) or sub-section (7) of section 8 or section 58B or sub-section (2A) of section 60” shall be substituted;

(ii) in the first proviso,—

(a) for the words “Adjudicating Authority”, the words “Special Court or the Adjudicating Authority, as the case may be,” shall be substituted;

(b) after the words “or seized”, the words “or frozen” shall be inserted.

8. In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), for the words, brackets and figures "sub-section (6) of section 8", the words, brackets, figures and letters "sub-section (5) or sub-section (6) or sub-section (7) of section 8 or section 58B or sub-section (2A) of section 60" shall be substituted.

Amendment  
of section 10.

9. For section 12 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution  
of new  
section for  
section 12.

"12. (1) Every reporting entity shall —

Reporting  
entity to  
maintain  
records.

(a) maintain a record of all transactions, including information relating to transactions covered under clause (b), in such manner as to enable it to reconstruct individual transactions;

(b) furnish to the Director within such time as may be prescribed, information relating to such transactions, whether attempted or executed, the nature and value of which may be prescribed;

(c) verify the identity of its clients in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed;

(d) identify the beneficial owner, if any, of such of its clients, as may be prescribed;

(e) maintain record of documents evidencing identity of its clients and beneficial owners as well as account files and business correspondence relating to its clients.

(2) Every information maintained, furnished or verified, save as otherwise provided under any law for the time being in force, shall be kept confidential.

(3) The records referred to in clause (a) of sub-section (1) shall be maintained for a period of five years from the date of transaction between a client and the reporting entity.

(4) The records referred to in clause (e) of sub-section (1) shall be maintained for a period of five years after the business relationship between a client and the reporting entity has ended or the account has been closed, whichever is later.

(5) The Central Government may, by notification, exempt any reporting entity or class of reporting entities from any obligation under this Chapter."

10. After section 12 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of  
new section  
12A.

"12A. (1) The Director may call for from any reporting entity any of the records referred to in sub-section (1) of section 12 and any additional information as he considers necessary for the purposes of this Act.

Access to  
information.

(2) Every reporting entity shall furnish to the Director such information as may be required by him under sub-section (1) within such time and in such manner as he may specify.

(3) Save as otherwise provided under any law for the time being in force, every information sought by the Director under sub-section (1), shall be kept confidential."

11. In section 13 of the principal Act,—

Amendment  
of section 13.

(i) in sub-section (1), for the words, brackets and figures "call for records referred to in sub-section (1) of section 12 and may make such inquiry or cause such inquiry to be made, as he thinks fit", the words "make such inquiry or cause such inquiry to be made, as he thinks fit to be necessary, with regard to the obligations of the reporting



entity, under this Chapter” shall be substituted;

(ii) after sub-section (1), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

“(1A) If at any stage of inquiry or any other proceedings before him, the Director having regard to the nature and complexity of the case, is of the opinion that it is necessary to do so, he may direct the concerned reporting entity to get its records, as may be specified, audited by an accountant from amongst a panel of accountants, maintained by the Central Government for this purpose.

(1B) The expenses of, and incidental to, any audit under sub-section (1A) shall be borne by the Central Government.”;

(iii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(2) If the Director, in the course of any inquiry, finds that a reporting entity or its designated director on the Board or any of its employees has failed to comply with the obligations under this Chapter, then, without prejudice to any other action that may be taken under any other provisions of this Act, he may—

(a) issue a warning in writing; or

(b) direct such reporting entity or its designated director on the Board or any of its employees, to comply with specific instructions; or

(c) direct such reporting entity or its designated director on the Board or any of its employees, to send reports at such interval as may be prescribed on the measures it is taking; or

(d) by an order, impose a monetary penalty on such reporting entity or its designated director on the Board or any of its employees, which shall not be less than ten thousand rupees but may extend to one lakh rupees for each failure.”;

(iv) after sub-section (3), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

“*Explanation.*—For the purpose of this section, “accountant” shall mean a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949.”

38 of 1949.

Substitution of new section for section 14.

12. For section 14 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

No civil or criminal proceedings against reporting entity, its directors and employees in certain cases.

“14. Save as otherwise provided in section 13, the reporting entity, its directors and employees shall not be liable to any civil or criminal proceedings against them for furnishing information under clause (b) of sub-section (1) of section 12.”.

Substitution of new section for section 15.

13. For section 15 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Procedure and manner of furnishing information by reporting entities.

“15. The Central Government may, in consultation with the Reserve Bank of India, prescribe the procedure and the manner of maintaining and furnishing information by a reporting entity under sub-section (1) of section 12 for the purpose of implementing the provisions of this Act.”.

Amendment of section 17.

14. In section 17 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

(a) in clause (iii), after the word “money-laundering,” the word “or” shall be inserted;

(b) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(iv) is in possession of any property related to crime.”;

(c) in clause (d), after the words “such record or”, the words “property, if required or” shall be inserted;

(d) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that no search shall be conducted unless, in relation to the scheduled offence, a report has been forwarded to a Magistrate under section 157 of the Code of Criminal Procedure, 1973, or a complaint has been filed by a person, authorised to investigate the offence mentioned in the Schedule, before a Magistrate or court for taking cognizance of the scheduled offence, as the case may be, or in cases where such report is not required to be forwarded, a similar report of information received or otherwise has been submitted by an officer authorised to investigate a scheduled offence to an officer not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or equivalent being head of the office or Ministry or Department or Unit, as the case may be, or any other officer who may be authorised by the Central Government, by notification, for this purpose.”;

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1A) Where it is not practicable to seize such record or property, the officer authorised under sub-section (1), may make an order to freeze such property whereupon the property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned:

Provided that if, at any time before its confiscation under sub-section (5) or sub-section (7) of section 8 or section 58B or sub-section (2A) of section 60, it becomes practical to seize a frozen property, the officer authorised under sub-section (1) may seize such property.”;

(iii) in sub-section (2), after the words, “immediately after search and seizure” the words “or upon issuance of a freezing order” shall be inserted;

(iv) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(4) The authority seizing any record or property under sub-section (1) or freezing any record or property under sub-section (1A) shall, within a period of thirty days from such seizure or freezing, as the case may be, file an application, requesting for retention of such record or property seized under sub-section (1) or for continuation of the order of freezing served under sub-section (1A), before the Adjudicating Authority.”.

15. In section 18 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

Amendment  
of section 18.

“Provided that no search of any person shall be made unless, in relation to the scheduled offence, a report has been forwarded to a Magistrate under section 157 of the Code of Criminal Procedure, 1973, or a complaint has been filed by a person, authorised to investigate the offence mentioned in the Schedule, before a Magistrate or court for taking cognizance of the scheduled offence, as the case may be, or in cases where such report is not required to be forwarded, a similar report of information received or otherwise has been submitted by an officer authorised to investigate a scheduled offence to an officer not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or equivalent being head of the office or Ministry or Department or Unit, as the case may be, or any other officer who may be authorised by the Central Government, by notification, for this purpose.”;

Substitution of  
new sections  
for section 20  
and section 21.

16. For sections 20 and 21 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

Retention of  
property.

“20. (1) Where any property has been seized under section 17 or section 18 or frozen under sub-section (1A) of section 17 and the officer authorised by the Director in this behalf has, on the basis of material in his possession, reason to believe (the reason for such belief to be recorded by him in writing) that such property is required to be retained for the purposes of adjudication under section 8, such property may, if seized, be retained or if frozen, may continue to remain frozen, for a period not exceeding one hundred and eighty days from the day on which such property was seized or frozen, as the case may be.

(2) The officer authorised by the Director shall, immediately after he has passed an order for retention or continuation of freezing of the property for purposes of adjudication under section 8, forward a copy of the order along with the material in his possession, referred to in sub-section (1), to the Adjudicating Authority, in a sealed envelope, in the manner as may be prescribed and such Adjudicating Authority shall keep such order and material for such period as may be prescribed.

(3) On the expiry of the period specified in sub-section (1), the property shall be returned to the person from whom such property was seized or whose property was ordered to be frozen unless the Adjudicating Authority permits retention or continuation of freezing of such property beyond the said period.

(4) The Adjudicating Authority, before authorising the retention or continuation of freezing of such property beyond the period specified in sub-section (1), shall satisfy himself that the property is *prima facie* involved in money-laundering and the property is required for the purposes of adjudication under section 8.

(5) After passing the order of confiscation under sub-section (5) or sub-section (7) of section 8, the Court or the Adjudicating Authority, as the case may be, shall direct the release of all property other than the property involved in money-laundering to the person from whom such property was seized or the persons entitled to receive it.

(6) Where an order releasing the property has been made by the Court under sub-section (6) of section 8 or by the Adjudicating Authority under section 58B or sub-section (2A) of section 60, the Director or any officer authorised by him in this behalf may withhold the release of any such property for a period of ninety days from the date of such order, if he is of the opinion that such property is relevant for the appeal proceedings under this Act.

Retention of  
records.

21. (1) Where any records have been seized, under section 17 or section 18 or frozen under sub-section (1A) of section 17 and the Investigating Officer or any other officer authorised by the Director in this behalf has reason to believe that any of such records are required to be retained for any inquiry under this Act, such records may if seized, be retained or if frozen, may continue to remain frozen, for a period not exceeding one hundred and eighty days from the day on which such records were seized or frozen, as the case may be.

(2) The person, from whom records seized or frozen, shall be entitled to obtain copies of records.

(3) On the expiry of the period specified under sub-section (1), the records shall be returned to the person from whom such records were seized or whose records were ordered to be frozen unless the Adjudicating Authority permits retention or continuation of freezing of such records beyond the said period.

(4) The Adjudicating Authority, before authorising the retention or continuation of freezing of such records beyond the period specified in sub-section (1), shall satisfy himself that the records are required for the purposes of adjudication under section 8.

(5) After passing of an order of confiscation under sub-section (5) or sub-section (7) of section 8, the Adjudicating Authority shall direct the release of the records to the person from whom such records were seized.

(6) Where an order releasing the records has been made by the Court under sub-section (6) of section 8 or by the Adjudicating Authority under section 58B or sub-section (2A) of section 60, the Director or any other officer authorised by him in this behalf may withhold the release of any such record for a period of ninety days from the date of such order, if he is of the opinion that such record is relevant for the appeal proceedings under this Act."

17. In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "a survey or a search," the words "or where any record or property is produced by any person or has been resumed or seized from the custody or control of any person or has been frozen under this Act or under any other law for the time being in force," shall be inserted. Amendment of section 22.

18. In section 23 of the principal Act, for the words and figure "under section 8, it shall, unless otherwise proved to the satisfaction of the Adjudicating Authority", the words and figure "under section 8 or for the trial of the money-laundering offence, it shall unless otherwise proved to the satisfaction of the Adjudicating Authority or the Special Court" shall be substituted. Amendment of section 23.

19. For section 24 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Amendment of section 24.

"24. In any proceeding relating to proceeds of crime under this Act,—

(a) in the case of a person charged with the offence of money-laundering under section 3, the Authority or Court shall, unless the contrary is proved, presume that such proceeds of crime are involved in money-laundering; and

(b) in the case of any other person the Authority or Court, may presume that such proceeds of crime are involved in money-laundering."

Burden of Proof.

20. In section 26 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "banking company, financial institution or intermediary", the words "reporting entity" shall be substituted. Amendment of section 26.

21. In section 44 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) an offence punishable under section 4 and any scheduled offence connected to the offence under that section shall be triable by the Special Court constituted for the area in which the offence has been committed:

Provided that the Special Court, trying a scheduled offence before the commencement of this Act, shall continue to try such scheduled offence; or";

(ii) in clause (b), for the words "cognizance of the offence for which the accused is committed to it for trial", the words and figure "cognizance of offence under section 3, without the accused being committed to it for trial" shall be substituted;

(iii) after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(c) if the court which has taken cognizance of the scheduled offence is other than the Special Court which has taken cognizance of the complaint of the

Amendment of section 44.

offence of money-laundering under sub-clause (b), it shall, on an application by the authority authorised to file a complaint under this Act, commit the case relating to the scheduled offence to the Special Court and the Special Court shall, on receipt of such case proceed to deal with it from the stage at which it is committed.

(d) a Special Court while trying the scheduled offence or the offence of money-laundering shall hold trial in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, as it applies to a trial before a Court of Session.” 2 of 1974.

Amendment of section 50. 22. In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b), for the words “banking company or a financial institution or a company,” the words “reporting entity” shall be substituted.

Amendment of section 54. 23. In section 54 of the principal Act,—

(i) in the opening portion, for the word “officers”, the words “officers and others” shall be substituted;

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) members of the recognised stock exchange referred to in clause (f) of section 2 and the officers of the stock exchanges recognised under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956; 42 of 1956.

(iii) after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(ha) officers of the Insurance Regulatory and Development Authority established under section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999; 41 of 1999.

(hb) officers of the Forward Markets Commission established under section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952; 74 of 1952.

(hc) officers and members of the recognised association recognised under section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952; 74 of 1952.

(hd) officers of the Pension Fund Regulatory and Development Authority;

(he) officers of the Department of Posts in the Government of India;

(hf) Registrars or Sub-Registrars appointed by the State Governments under section 6 of the Registration Act, 1908; 16 of 1908.

(hg) registering authority empowered to register motor vehicles under Chapter IV of the Motor Vehicles Act, 1988; 59 of 1988.

(hh) officers and members of the Institute of Chartered Accountants of India constituted under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949; 38 of 1949.

(hi) officers and members of the Institute of Cost and Works Accountants of India constituted under section 3 of the Cost and Works Accountants Act, 1959; 23 of 1959.

(hj) officers and members of the Institute of Company Secretaries of India constituted under section 3 of the Company Secretaries Act, 1980; 56 of 1980.

(iv) in clause (j), for the words “banking companies”, the words “reporting entities” shall be substituted.

24. After section 58, the following sections shall be inserted, namely:—

Insertion of  
new sections  
58A and 58B.

“58A. Where on closure of the criminal case or conclusion of a trial in a criminal court outside India under the corresponding law of any other country, such court finds that the offence of money-laundering has not taken place or the property in India is not involved in money-laundering, the Special Court may, on an application moved by the concerned person or the Director, after notice to the other party, order release of such property to the person entitled to receive it.

Special Court  
to release the  
property.

58B. Where the trial under the corresponding law of any other country cannot be conducted by reason of the death of the accused or the accused being declared a proclaimed offender or for any other reason or having commenced but could not be concluded, the Central Government shall, on receipt of a letter of request from a court or authority in a contracting State requesting for confiscation or release of property, as the case may be, forward the same to the Director to move an application before the Special Court and upon such application the Special Court shall pass appropriate orders regarding confiscation or release of such property involved in the offence of money-laundering.”

Letter of  
request of a  
contracting  
State or  
authority for  
confiscation  
or release the  
property.

25. In section 60 of the principal Act,—

Amendment  
of section 60.

(i) in sub-section (1), for the words and figures “property under section 5 or where an Adjudicating Authority has made an order confirming such attachment or confiscation of any property under section 8”, the words, figures, brackets and letter “property under section 5 or for freezing under sub-section (14) of section 17 or where an Adjudicating Authority has made an order relating to a property under section 8 or where a Special Court has made an order of confiscation relating to a property under sub-section (5) or sub section (6) of section 8” shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),—

(a) for the words “attachment or confiscation”, the words “attachment, seizure, freezing or confiscation” shall be substituted;

(b) for the word and figure “section 3”, the words “a corresponding law” shall be substituted;

(iii) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2A) Where on closure of the criminal case or conclusion of trial in a criminal court outside India under the corresponding law of any other country, such court finds that the offence of money-laundering under the corresponding law of that country has been committed, the Adjudicating Authority shall, on receipt of an application from the Director for execution of confiscation under sub-section (2), order, after giving notice to the affected persons, that such property involved in money-laundering or which has been used for commission of the offence of money-laundering stand confiscated to the Central Government.”

26. In section 63 of the principal Act, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment  
of section 63.

“(4) Notwithstanding anything contained in clause (c) of sub-section (2), a person who intentionally disobeys any direction issued under section 50 shall also be liable to be proceeded against under section 174 of the Indian Penal Code.”

Substitution  
of new  
section for  
section 69.

27. For section 69 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Recovery of  
fine or  
penalty.

“69. Where any fine or penalty imposed on any person under section 13 or section 63 is not paid within six months from the day of imposition of fine or penalty, the Director or any other officer authorised by him in this behalf may proceed to recover the amount from the said person in the same manner as prescribed in Schedule II of the Income-tax Act, 1961 for the recovery of arrears and he or any officer authorised by him in this behalf shall have all the powers of the Tax Recovery Officer mentioned in the said Schedule for the said purpose.”

43 of 1961.

Amendment  
of section 70.

28. In section 70 of the principal Act, the *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof and after *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

“*Explanation 2.*—For the removal of doubts, it is hereby clarified that a company may be prosecuted, notwithstanding whether the prosecution or conviction of any legal juridical person shall be contingent on the prosecution or conviction of any individual.”

Amendment  
of section 73.

29. In section 73 of the principal Act, in sub-section (2),—

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

“(aa) the manner of provisional attachment of property under sub-section (1) of section 5;”;

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ee) the manner of seizing or taking possession of property attached under section 5 or frozen under sub-section (1A) of section 17 or under sub-section (4) of section 8;”;

(iii) clause (h) shall be omitted;

(iv) in clause (i), for the words “the time within which”, the words “the nature and value of transactions and the time within which” shall be substituted;

(v) for clause (j), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(j) the manner and the conditions in which identity of clients shall be verified by the reporting entities under clause (c) of sub-section (1) of section 12;

(jj) the manner of identifying beneficial owner, if any, from the clients by the reporting entities under clause (d) of sub-section (1) of section 12;

(jjj) the period of interval in which the reports are sent by the reporting entities or any of its employees under clause (c) of sub-section (2) of section 13;”;

(vi) after clause (p), the following clause shall be inserted, namely:—

“(pp) the manner in which the forwarding of the order for retention or continuation of freezing of the property and the period of keeping such order and material under sub-section (2) of section 20;”.

30. In the Schedule to the principal Act,—

(i) for Part A, the following Part shall be substituted, namely:—

Amendment  
of the  
Schedule.

“PART A

PARAGRAPH 1

OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE

(45 OF 1860)

Section	Description of offence
120B	Criminal conspiracy.
121	Waging or attempting to wage war or abetting waging of war, against the Government of India.
121A	Conspiracy to commit offences punishable by section 121 against the State.
255	Counterfeiting Government stamp.
257	Making or selling instrument for counterfeiting Government stamp.
258	Sale of counterfeit Government stamp.
259	Having possession of counterfeit Government stamp.
260	Using as genuine a Government stamp known to be counterfeit.
302	Murder.
304	Punishment for culpable homicide not amounting to murder.
307	Attempt to murder.
308	Attempt to commit culpable homicide.
327	Voluntarily causing hurt to extort property, or to constrain to an illegal act.
329	Voluntarily causing grievous hurt to extort property, or to constrain to an illegal act.
364A	Kidnapping for ransom, etc.
384 to 389	Offences relating to extortion.
392 to 402	Offences relating to robbery and dacoity.
411	Dishonestly receiving stolen property.
412	Dishonestly receiving property stolen in the commission of a dacoity.
413	Habitually dealing in stolen property.
414	Assisting in concealment of stolen property.
417	Punishment for cheating.
418	Cheating with knowledge that wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect.
419	Punishment for cheating by personation.
420	Cheating and dishonestly inducing delivery of property.
421	Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors.



14	THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY	[PART II—
Section	Description of offence	
422	Dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors.	
423	Dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration.	
424	Dishonest or fraudulent removal or concealment of property.	
467	Forgery of valuable security, will, etc.	
471	Using as genuine a forged document or electronic record.	
472 and 473	Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery.	
475 and 476	Counterfeiting device or mark.	
481	Using a false property mark.	
482	Punishment for using a false property mark.	
483	Counterfeiting a property mark used by another.	
484	Counterfeiting a mark used by a public servant.	
485	Making or possession of any instrument for counterfeiting a property mark.	
486	Selling goods marked with a counterfeit property mark.	
487	Making a false mark upon any receptacle containing goods.	
488	Punishment for making use of any such false mark.	
489A	Counterfeiting currency notes or bank notes.	
489B	Using as genuine, forged or counterfeit currency notes or bank notes.	

## PARAGRAPH 2

OFFENCES UNDER THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES  
ACT, 1985

(61 OF 1985)

Section	Description of offence
15	Contravention in relation to poppy straw.
16	Contravention in relation to coca plant and coca leaves.
17	Contravention in relation to prepared opium.
18	Contravention in relation to opium poppy and opium.
19	Embezzlement of opium by cultivator.
20	Contravention in relation to cannabis plant and cannabis.
21	Contravention in relation to manufactured drugs and preparations.
22	Contravention in relation to psychotropic substances.
23	Illegal import into India, export from India to transshipment of narcotic drugs and psychotropic substances.
24	External dealings in narcotic drugs and psychotropic substances in contravention of section 12 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

SEC. 1]

## THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

15

Section	Description of offence
25A	Contravention of orders made under section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
27A	Financing illicit traffic and harbouring offenders.
29	Abetment and criminal conspiracy.

## PARAGRAPH 3

OFFENCES UNDER THE EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT, 1908

(6 OF 1908)

Section	Description of offence
3	Causing explosion likely to endanger life or property.
4	Attempt to cause explosion, or for making or keeping explosives with intent to endanger life or property.
5	Making or possessing explosives under suspicious circumstances.

## PARAGRAPH 4

OFFENCES UNDER THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

(37 OF 1967)

Section	Description of offence
10 read with section 3	Penalty for being member of an unlawful association, etc.
11 read with section 3	Penalty for dealing with funds of an unlawful association.
13 read with section 3	Punishment for unlawful activities.
16 read with section 15	Punishment for terrorist act.
16A	Punishment for making demands of radioactive substances, nuclear devices, etc.
17	Punishment for raising fund for terrorist act.
18	Punishment for conspiracy, etc.
18A	Punishment for organising of terrorist camps.
18B	Punishment for recruiting of any person or persons for terrorist act.
19	Punishment for harbouring, etc.
20	Punishment for being member of terrorist gang or organisation.
21	Punishment for holding proceeds of terrorism.
38	Offence relating to membership of a terrorist organisation.
39	Offence relating to support given to a terrorist organisation.
40	Offence of raising fund for a terrorist organisation.

## PARAGRAPH 5

## OFFENCES UNDER THE ARMS ACT, 1959

(54 OF 1959)

Section	Description of offence
25	<p>To manufacture, sell, transfer, convert, repair or test or prove or expose or offer for sale or transfer or have in his possession for sale, transfer, conversion, repair, test or proof, any arms or ammunition to contravention of section 5 of the Arms Act, 1959.</p> <p>To acquire, have in possession or carry any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7 of the Arms Act, 1959.</p> <p>Contravention of section 24A of the Arms Act, 1959 relating to prohibition as to possession of notified arms in disturbed areas, etc.</p> <p>Contravention of section 24B of the Arms Act, 1959 relating to prohibition as to carrying of notified arms in or through public places in disturbed areas.</p> <p>Other offences specified in section 25.</p>
26	<p>To do any act in contravention of any provisions of section 3, 4, 10 or section 12 of the Arms Act, 1959 in such manner as specified in sub-section (1) of section 26 of the said Act.</p> <p>To do any act in contravention of any provisions of section 5, 6, 7 or section 11 of the Arms Act, 1959 in such manner as specified in sub-section (2) of section 26 of the said Act.</p> <p>Other offences specified in section 26.</p>
27	Use of arms or ammunition in contravention of section 5 or use of any arms or ammunition in contravention of section 7 of the Arms Act, 1959.
28	Use and possession of fire arms or imitation fire arms in certain cases.
29	Knowingly purchasing arms from unlicensed person or for delivering arms, etc., to person not entitled to possess the same.
30	Contravention of any condition of a licence or any provisions of the Arms Act, 1959 or any rule made thereunder.

## PARAGRAPH 6

## OFFENCES UNDER THE WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1972

(53 OF 1972)

Section	Description of offence
51 read with section 9	Hunting of wild animals.
51 read with section 17A	Contravention of provisions of section 17A relating to prohibition of picking, uprooting, etc., of specified plants.

SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

17

Section	Description of offence
51 read with section 39	Contravention of provisions of section 39 relating to wild animals, etc., to be Government property.
51 read with section 44	Contravention of provisions of section 44 relating to dealings in trophy and animal articles without licence prohibited.
51 read with section 48	Contravention of provisions of section 48 relating to purchase of animal, etc., by licensee.
51 read with section 49B	Contravention of provisions of section 49B relating to prohibition of dealings in trophies, animals articles, etc., derived from scheduled animals.

## PARAGRAPH 7

OFFENCES UNDER THE IMMORAL TRAFFIC (PREVENTION) ACT, 1956

(104 OF 1956)

Section	Description of offence
5	Procuring, inducing or taking person for the sake of prostitution.
6	Detaining a person in premises where prostitution is carried on.
8	Seducing or soliciting for purpose of prostitution.
9	Seduction of a person in custody.

## PARAGRAPH 8

OFFENCES UNDER THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

(49 OF 1988)

Section	Description of offence
7	Public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act.
8	Taking gratification in order, by corrupt or illegal means, to influence public servant.
9	Taking gratification for exercise of personal influence with public servant.
10	Abetment by public servant of offences defined in section 8 or section 9 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
13	Criminal misconduct by a public servant.

## PARAGRAPH 9

OFFENCES UNDER THE EXPLOSIVES ACT, 1884

(4 OF 1884)

Section	Description of offence
9B	Punishment for certain offences.
9C	Offences by companies.

## PARAGRAPH 10

## OFFENCES UNDER THE ANTIQUITIES AND ARTS TREASURES ACT, 1972

(52 OF 1972)

Section	Description of offence
25 read with section 3	Contravention of export trade in antiquities and art treasures.
28	Offences by companies.

## PARAGRAPH 11

## OFFENCES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ACT, 1992

(15 OF 1992)

Section	Description of offence
12A read with section 24	Prohibition of manipulative and deceptive devices, insider trading and substantial.
24	Acquisition of securities or control.

## PARAGRAPH 12

## OFFENCES UNDER THE CUSTOMS ACT, 1962

(52 OF 1962)

Section	Description of offence
135	Evasion of duty or prohibitions.

## PARAGRAPH 13

## OFFENCES UNDER THE BONDED LABOUR SYSTEM (ABOLITION) ACT, 1976

(19 OF 1976)

Section	Description of offence
16	Punishment for enforcement of bonded labour.
18	Punishment for extracting bonded labour under the bonded labour system.
20	Abetment to be an offence.

## PARAGRAPH 14

## OFFENCES UNDER THE CHILD LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) ACT, 1986

(61 OF 1986)

Section	Description of offence
14	Punishment for employment of any child to work in contravention of the provisions of section 3.

## PARAGRAPH 15

OFFENCES UNDER THE TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS ACT, 1994  
(42 OF 1994)

Section	Description of offence
18	Punishment for removal of human organ without authority.
19	Punishment for commercial dealings in human organs.
20	Punishment for contravention of any other provisions of this Act.

## PARAGRAPH 16

OFFENCES UNDER THE JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2000  
(56 OF 2000)

Section	Description of offence
23	Punishment for cruelty to juvenile or child.
24	Employment of juvenile or child for begging.
25	Penalty for giving intoxicating liquor or narcotic drug or psychotropic substance to juvenile or child.
26	Exploitation of juvenile or child employee.

## PARAGRAPH 17

OFFENCES UNDER THE EMIGRATION ACT, 1983  
(31 OF 1983)

Section	Description of offence
24	Offences and penalties.

## PARAGRAPH 18

OFFENCES UNDER THE PASSPORTS ACT, 1967  
(15 OF 1967)

Section	Description of offence
12	Offences and penalties.

## PARAGRAPH 19

OFFENCES UNDER THE FOREIGNERS ACT, 1946  
(31 OF 1946)

Section	Description of offence
14	Penalty for contravention of provisions of the Act, etc.
14B	Penalty for using forged passport.
14C	Penalty for abetment.

## PARAGRAPH 20

## OFFENCES UNDER THE COPYRIGHT ACT, 1957

(14 OF 1957)

Section	Description of offence
63	Offence of infringement of copyright or other rights conferred by this Act.
63A	Enhanced penalty on second and subsequent convictions.
63B	Knowing use of infringing copy of computer programme.
68A	Penalty for contravention of section 52A.

## PARAGRAPH 21

## OFFENCES UNDER THE TRADE MARKS ACT, 1999

(47 OF 1999)

Section	Description of offence
103	Penalty for applying false trade marks, trade descriptions, etc.
104	Penalty for selling goods or providing services to which false trade mark or false trade description is applied.
105	Enhanced penalty on second or subsequent conviction.
107	Penalty for falsely representing a trade mark as registered.
120	Punishment of abetment in India of acts done out of India.

## PARAGRAPH 22

## OFFENCES UNDER THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000

(21 OF 2000)

Section	Description of offence
72	Penalty for breach of confidentiality and privacy.
75	Act to apply for offence or contravention committed outside India.

## PARAGRAPH 23

## OFFENCES UNDER THE BIOLOGICAL DIVERSITY ACT, 2002

(18 OF 2003)

Section	Description of offence
55 read with section 6.	Penalties for contravention of section 6, etc.

## PARAGRAPH 24

## OFFENCES UNDER THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

( 53 OF 2001)

Section	Description of offence
70 read with section 68	Penalty for applying false denomination, etc.
71 read with section 68	Penalty for selling varieties to which false denomination is applied.
72 read with section 68	Penalty for falsely representing a variety as registered.
73 read with section 68	Penalty for subsequent offence.

## PARAGRAPH 25

## OFFENCES UNDER THE ENVIRONMENT PROTECTION ACT, 1986

( 29 OF 1986)

Section	Description of offence
15 read with section 7	Penalty for discharging environmental pollutants, etc., in excess of prescribed standards.
15 read with section 8	Penalty for handling hazardous substances without complying with procedural safeguards.

## PARAGRAPH 26

## OFFENCES UNDER THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

( 6 OF 1974)

Section	Description of offence
41(2)	Penalty for pollution of stream or well.
43	Penalty for contravention of provisions of section 24.

## PARAGRAPH 27

## OFFENCES UNDER THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981

( 14 OF 1981)

Section	Description of offence
37	Failure to comply with the provisions for operating industrial plant.



## PARAGRAPH 28

OFFENCES UNDER THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST SAFETY OF MARITIME  
NAVIGATION AND FIXED PLATFORMS ON CONTINENTAL SHELF  
ACT, 2002

(69 OF 2002)

Section	Description of offence
3	Offences against ship, fixed platform, cargo of a ship, maritime navigational facilities, etc.”;

(ii) in Part B, paragraphs 1 to 25 shall be omitted;

(iii) in Part C, serial number (2) and the entries relating thereto shall be omitted.

P.K. MALHOTRA,  
Secy. to the Govt. of India.

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur,  
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Pritam Chand, aged 42 years s/o Shri Dhani Ram, r/o Village Sawahl Ghara, P.O. Ropa, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Babli Devi, aged 35 years d/o Shri Ram Lal, r/o Village Taran, P. O. Ishwar Nagar, Tehsil Kot Mangal Singh Taran Road, District Amritsar (PB). . . *Applicants.*

*Versus*

General public

*Subject.*—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Pritam Chand and Smt. Babli Devi have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 1-10-2009 at Gasota Mahadev Mandir, Hamirpur (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-2-2014. The objection received after 12-2-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-12-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Satish Kumar Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional  
Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh,**

In the matter of :

1. Shri Vikas Thakur, aged 25 years s/o Shri Shamsher Singh, r/o Village Chapruhi, P. O. Pir Saluhi, Tehsil Rakkar, District Kangra (H. P.).

2. Arti Sharma, aged 20 years d/o Shri Ramesh Chand, r/o VPO Choli, Tehsil Rakkar, District Kangra (H. P.) at present c/o Gopal Singh s/o Shri Kanshi Ram, r/o Shiv Nagar, Ward No. 4, Hamirpur (H. P.) . . *Applicants.*

*Versus*

General public

*Subject.*—Notice of the Intended Marriage.

Shri Vikas Thakur and Arti Sharma have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 29-1-2014. The objection received after 29-1-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-12-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Satish Kumar Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional  
Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Swarup Chand, aged 30 years s/o Shri Parkash Chand, r/o Village Gujrehra, P. O. Chabutra, Tehsil Sujampur, District Hamirpur (H. P.).
2. Santosh Kumari, aged 22 years d/o Shri Gian Chand, r/o Village Kothi, P.O. Karara, Tehsil and District Hamirpur (H. P.) . . . *Applicants.*

*Versus*

General public

*Subject.*—Notice of the Intended Marriage.

Shri Swarup Chand and Santosh Kumari have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 10-2-2014. The objection received after 10-2-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-12-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur,  
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Pankaj Sharma, aged 27 years s/o Shri Hukam Chand, r/o Village Ghanal, P. O., Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Neetu Devi, aged 30 years d/o Shri Kashmir Singh, r/o Village Daboh, P.O. Bagwara, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

*Versus*

General public

*Subject.*—Notice of the Intended Marriage.

Shri Pankaj Sharma and Neetu Devi have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-10-2013 at Mata Mandir, Tauni Devi, Distirct Hamirpur (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 5-3-2014. The objection received after 5-3-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-12-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Satish Kumar Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional  
Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Sanjay Kumar, aged 29 years s/o Shri Kehar Singh, r/o Village Bag Chauki, P. O. Kuthera, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Aneeta Kumari, aged 22 years d/o Shri Sita Ram, r/o Village Dialri, P.O. Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) . . Applicants.

*Versus*

General public

*Subject.*—Notice of the Intended Marriage.

Shri Sanjay Kumar and Aneeta Kumari have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 27-1-2014. The objection received after 27-1-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-12-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

---

**In the Court of Shri Satish Kumar Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Rajesh Kumar, aged 25 years s/o Shri Partap Chand, r/o Village Harsan, P. O. Kakriar, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Mamta Devi, aged 18 years d/o Shri Sarwan Kumar, r/o Village Gahri, P.O. Kakar, Tehsil Sujampur, District Hamirpur (H. P.) .. *Applicants.*

*Versus*

General public

*Subject.*—Notice of the Intended Marriage.

Shri Rajesh Kumar and Mamta Devi have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 19-2-2014. The objection received after 19-2-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-12-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

---

**In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Kamal Manohar Khanna s/o Shri Bansi Lal Khanna, r/o Geeta Cottage, Shimla, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

*Versus*

General Public

.. *Respondent.*

*Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Whereas Shri Kamal Manohar Khanna s/o Shri Bansi Lal Khanna, r/o Geeta Cottage, Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of date of death of his mother namely Smt. Maya Devi Khanna whose date of death is 27-11-2009 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 9th day of January, 2014.

Seal.

G. C. NEGI,  
*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.*

---

**In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),  
District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Jitender Verma s/o Shri Bali Ram, r/o Village Bhekhlti, P. O. Fagu, Tehsil Theog,  
District Shimla, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

*Versus*

General Public

.. *Respondent.*

*Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Whereas Shri Jitender Verma s/o Bali Ram, r/o Village Bhekhlti, P. O. Fagu, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of his son namely Kartike whose date of birth is 25-4-2009 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of name and date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court within one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and the case will be decided accordingly.

Given under my hand and the seal of the Court on this 10th day of January, 2014.

Seal.

G. C. NEGI,  
*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.*